जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

epaper.rashtradoot.com

बीकानेर

Rashtradoot

फोनः- 2200660 फैक्स : 0151-2527371 वर्षः 47 संख्याः 169 प्रभात बीकानेर, रविवार 11 जनवरी, 2026 डाक प.स.बीकानेर/045/2020-22 पृष्ठ 8 मूल्य 2.50 रु.

'ईडी कार्यवाही आदि, बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए की जा रही है'

ममता बनर्जी का खेमा आक्रामक मुद्रा में यह भी कह रहा है कि केन्द्रीय सरकार का यह प्लान हम सफल नहीं होने देंगे

-रेणु मित्तल-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 10 जनवरी। पश्चिम बंगाल का सियासी पारा उफान पर है। ममता बनर्जी ने भाजपा को चुनौती दी है कि वह उन्हें अस्थिर करके दिखाए। वह भाजपा के साथ सीधी लड़ाई में हैं और हर मोर्चे पर हमला करने के लिए तैयार हैं।

दिल्ली में इस बात को लेकर अटकलें तेज़ हैं कि भाजपा पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की ज़मीन कैसे तैयार कर रही है। ईडी द्वारा आई-पैक के दफ्तर पर छापे के बाद वहां से फाइलें और डेटा उठाने को लेकर भाजपा ममता बनर्जी पर हमला कर रही है।

ममता बनर्जी खुद आई-पैक के दफ्तर पहुंचीं और फाइलें उठा ले गईं। उनका कहना है कि ये फाइलें उनकी

- **ऐसा लग रहा है, ममता बनर्जी व केन्द्रीय सरकार के बीच ''युद्ध'' तब तक चलेगा, जब तक बंगाल चुनाव का अंतिम वोट नहीं पड़ जाता।**
- **ममता बनर्जी के लोग अपने इस तर्क को आगे ले जाते हुए, यह दावा भी कर रहे हैं कि भाजपा (केन्द्रीय सरकार) के द्वारा राष्ट्रपति शासन लगाने के बाद ममता बनर्जी के वफादार कार्यकर्ता व नेता तथा प्रशासन असक्षम हो जाएंगे, चुनाव में भूमिका निभाने की दृष्टि से तथा भाजपा अपने मन मुताबिक चुनाव का संचालन कर सकेगी और यह ममता बनर्जी के समर्थक, कदापि नहीं होने देंगे।**

पार्टी तृणमूल कांग्रेस से जुड़े चुनावी डेटा और चुनावी जानकारियों से संबंधित हैं, जिन पर अमित शाह की नज़र है।

ईडी ने इस पर सफाई दी है कि यह कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले से जुड़ी है, न कि किसी राजनीतिक पार्टी से।

ममता, जिनका लड़ने का जज़्बा फिर से जाग उठा है, सड़कों पर उतर आई हैं और अपने समर्थकों के साथ मार्च कर रही हैं। वह यह संदेश दे रही हैं कि भाजपा जो भी करेगी, वह उससे लड़ने के लिए तैयार हैं और डरने वाली नहीं हैं।

सूत्रों का कहना है कि भाजपा राष्ट्रपति शासन लगाने का विकल्प तलाश रही है, ताकि ममता के वफादारों और उनकी प्रशासनिक मशीनरी के सहयोग के बिना चुनाव कराए जा सकें और केंद्र की भाजपा सरकार को चुनाव संभालने और उन्हें प्रभावित करने की पूरी छूट मिल सके।

यह लड़ाई आखिरी वोट पड़ने तक चलती रहेगी, जहां भाजपा ममता बनर्जी को अस्थिर करने के लिए पूरी ताकत झोंक देगी और ममता भी उतनी ही दृढ़ता से पश्चिम बंगाल से भाजपा को बाहर करने के लिए डटी रहेंगी।

एसआई भर्ती में आयु सीमा की छूट पर हाई कोर्ट 31 मार्च तक निर्णय लेगा

जयपुर, 10 जनवरी। सुप्रीम कोर्ट ने एसआई भर्ती-2021 में शामिल हुए अभ्यर्थियों को साल 2025 की एसआई भर्ती में आयु सीमा में छूट से जुड़े मामले में दायर एसएलपी को निस्तारित कर दिया है। अदालत ने कहा है कि 2021 की भर्ती को रद्द करने वाले एकलपीठ के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट की खंडपीठ पहले से ही सुनवाई कर रही है। ऐसे में आयु सीमा में छूट से जुड़े मुद्दे पर हाईकोर्ट की खंडपीठ 31 मार्च से पहले फैसला करे।

- **सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में दायर एसएलपी का निस्तारण किया।**

जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चन्द्र शर्मा की खंडपीठ ने यह आदेश सूरज मल मीणा की ओर से दायर एसएलपी का निस्तारण करते हुए दिए।

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि एसआई 2021 भर्ती को रद्द करने के संबंध में निर्णय हो जाता है तो आयु सीमा का विवाद स्वत: ही समाप्त हो जाएगा, लेकिन यदि भर्ती रद्द नहीं होती है तो हाईकोर्ट की खंडपीठ के निर्णय के आधार पर आयु सीमा में छूट का फैसला होगा।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

ईडी सुप्रीम कोर्ट पहुँचा, ममता बनर्जी के खिलाफ कार्यवाही की गुहार लेकर

पर, आश्चर्य की बात यह है कि ईडी की गुहार में ममता जी को गिरफ्तार करने के लिए मांग नहीं की गई, बल्कि यह मांग की गई है कि ईडी को उसका काम करने दिया जाए, उसमें बाधाएं नहीं होने दें

- अंजन रॉय -
- राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो -

नई दिल्ली, 10 जनवरी। अपनी कार्यवाही में लगातार बाधा डाले जाने और कलकत्ता उच्च न्यायालय से कोई राहत न मिलने से खिन्न एनफोर्समैंट डायरैक्टोरेट (ईडी) ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। यह मामला कई करोड़ रु. के कोयला घोटाले से जुड़ा है, जिसमें एक कंसल्टेंसी फर्म के कार्यालयों में तलाशी और दस्तावेजों की जब्ती की ईडी की कोशिश विफल कर दी गई थी।

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार को जो किया, ऐसा भारत में पहली बार हुआ है। वे कोलकाता में आई पैक नामक फर्म के मालिक के आवास और शहर में स्थित उसके मुख्यालय से कथित आपत्तिजनक सामग्री और सबूत अपने

- **ईडी ने (केन्द्रीय सरकार ने) इतना नरम रवैया क्यों अख्तियार किया। ममता बनर्जी ने सरकारी एजेंसी के काम में पुलिस की मदद से बाधा पहुंचायी और सबूत के कागज़ात का ''डेटा'' उठाकर ले गईं। यह अपने आप में गंभीर जुर्म है और अगर कोई साधारण व्यक्ति यह अपराध करता तो उसे तुरंत जेल भेज कर दंडात्मक कार्यवाही की जाती।**

साथ ले गईं। यह पहली बार है जब किसी सत्तारूढ़ मुख्यमंत्री ने राज्य पुलिस के साथ आकर ईडी को उसके वैधानिक कर्तव्य का पालन करने से रोका।

वह भी एक गंभीर आर्थिक अपराध के मामले में, जिसमें अवैध कोयला खनन और हवाला लेनदेन के ज़रिये बिक्री की रकम को इधर-उधर करने के आरोप हैं। ईडी यह जांच प्रिवैशन ऑफ मनी लॉण्डरिंग एक्ट (पीएमएलए) के तहत कर रही थी।

इस तरह का कृत्य कानून की सामान्य प्रक्रिया में ही अपराध की श्रेणी में आता है। लेकिन जिस तरह से ममता बनर्जी ने हस्तक्षेप किया और कथित तौर पर मामले से जुड़े महत्वपूर्ण सबूत अपने साथ ले गईं, वह स्वयं कानून का स्पष्ट उल्लंघन था। वास्तव में उन्होंने राज्य पुलिस के एक दल के साथ ईडी की टीम पर हमला किया और उसे डराने-धमकाने का काम किया, जबकि एजेंसी

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

भारत-अमेरिका व्यापारिक वार्ता में अवरोध से भारी घबराहट है निर्यातकों में

निर्यातकों ने भारत सरकार व अमेरिका से वार्ता पुनः शुरु करने का आग्रह किया

- सुकुमार साह -
- राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो -

नई दिल्ली, 10 जनवरी। भारत के निर्यातकों ने नई दिल्ली और वॉशिंगटन से तत्काल फिर से बातचीत करने की अपील की है। उन्होंने चेतावनी दी है कि द्विपक्षीय व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने में हो रही देरी से पहले ही नुकसान हो रहा है। और यदि टैरिफ का दबाव और बढ़ा तो यह नुकसान और बढ़ जाएगा। अमेरिका द्वारा चुनिंदा भारतीय वस्तुओं पर 50 प्रतिशत तक का शुल्क लगाए जाने के बाद, उद्योग संगठनों का तर्क है कि दांव पर सिर्फ एक व्यापार समझौता नहीं, बल्कि भारत के सबसे बड़े निर्यात बाज़ार में उसके निर्यात क्षेत्र की प्रतिस्पर्धात्मकता भी लगी हुई है।

फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गनाइजेशंस (एफआईईओ) के

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

- **फैडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गनाइज़ेशन के अध्यक्ष एससी रल्हन ने निर्यातकों के बीच बढ़ती हताशा और भय का हवाला देते हुए कहा कि दोनों पक्षों को परस्पर हित के लिए व्यापारिक समझौता करना चाहिए और उससे संबंधित मसलों का समाधान करना चाहिए।**
- **भारत के कुल निर्यात का लगभग 20 प्रतिशत अमेरिका को जाता है, इनमें टैक्सटाइल, लैदर, जवाहरात, इंजीनियरिंग वस्तुएं, ऑटो पार्ट्स व कैमिकल शामिल हैं। यह क्षेत्र 50 प्रतिशत टैरिफ से पहले ही त्रस्त है और अगर ट्रेड डील नहीं हुई तो इन वस्तुओं को अमेरिका के बाज़ार से हटना पड़ेगा।**
- **निर्यातकों का कहना है कि बातचीत में निष्क्रियता से नुकसान बढ़ रहा है, लाभ का मार्जिन सिकुड़ रहा है, प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है, ऑर्डर कैंसल हो रहे हैं। ट्रेड डील मात्र प्रतीकात्मक नहीं है, बल्कि अस्तित्व से जुड़ी हुई है।**

जैसलमेर में पारा 2.2 डिग्री रहा

जैसलमेर, (निसं)। शनिवार को जैसलमेर प्रदेश का सबसे ठंडा इलाका रहा, जहाँ न्यूनतम तापमान 2.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। यह तापमान प्रदेश के सबसे ठंडे माने जाने वाले हिल स्टेशन माउंट आबू (5.7) से भी कम

- **मौसम विभाग ने अगले 2-3 दिन तक शीत लहर जारी रहने का येलो अलर्ट जारी किया।**

रहा। उत्तर की बर्फीली हवाओं के कारण सुबह के समय कड़ाके की ठंड का एहसास ज़ीरो डिग्री जैसा हो रहा था।

शनिवार अलसुबह जिला घने कोहरे की चादर में लिपटा नजर आया। विज़िबिलिटी बेहद कम होने के कारण चाचा गांव के पास एक निजी बस और पुलिस की गाड़ी में जोरदार भिड़ंत हो गई। इस हादसे में पुलिस की गाड़ी में भारी नुकसान हुआ। कोहरे के कारण सड़कों पर वाहनों की रफ्तार बेहद धीमी रही और लोग सुबह देर तक अलाव जलाकर आग तापते देखे गए। मौसम विभाग ने अगले दो-तीन दिनों तक घना कोहरा और शीत लहर जारी रहने का यलो अलर्ट जारी किया है।

महाराष्ट्र में नए समीकरण उभरेंगे, शहरी निकाय चुनावों के बाद

ठाकरे कज़िंस (उद्धव एवं राज ठाकरे) एक साथ आ गए हैं, चाचा-भतीजा (शरद पवार और अजित) ने भी चुनावी तालमेल कर लिया है

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 10 जनवरी। महाराष्ट्र की राजनीति इस समय अभूतपूर्व पुनर्गठन के दौर से गुजर रही है, क्योंकि राज्य की 29 नगर निकायों में होने वाले चुनावों की तैयारी चल रही है। ये चुनाव तय समय से चार साल की देरी से कराए जा रहे हैं।

इन बदलावों में सबसे अहम है, एक तो अलग हो चुके ठाकरे कज़िन्स (चचेरे भाइयों) का साथ आना और दूसरे प्रतिद्वंद्वी पवार गुटों के बीच सुलह की शुरुआती कोशिशें।

एक ऐसे घटनाक्रम में जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी, उद्धव ठाकरे की शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) ने महा विकास अघाडी (एमवीए) गठबंधन से नाता तोड़ते हुए मुंबई महानगरपालिका चुनावों के लिए चचेरे भाई राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) के साथ हाथ मिला लिया है।

- **ठाकरे परिवार की एकजुटता मात्र चुनावी लाभ के लिए नहीं, बल्कि वे बाल ठाकरे की विरासत और ''मराठी मानुस'' वोट बैंक पुनः पाना चाहते हैं। बीएमसी चुनावों में इस एकजुटता का क्या नतीज़ा निकलता है, इसी पर आगे का रास्ता निर्भर करेगा।**
- **एनसीपी के कर्ताधर्ता पवार परिवार में बढ़ती निकटता के पीछे शरद पवार की अपनी बेटी सुप्रिया सुले के भविष्य की चिंता मुख्य कारण है। वे जानते हैं, सुप्रिया उनके भतीजे अजित की तरह जनाधार वाली नेता नहीं हैं।**
- **यह भी चर्चा है कि एकजुट एनसीपी एनडीए में शामिल हो जाएगी। यहाँ राज्य में अजित पवार मुख्य भूमिका निभाएंगें और राष्ट्रीय स्तर पर सुप्रिया सुले।**

यह साझेदारी केवल चुनावी मजबूरी नहीं है, बल्कि दोनों ठाकरे भाइयों द्वारा मराठी राजनीति के दिग्गज बालासाहेब ठाकरे की विरासत को फिर से अपने नाम करने की रणनीतिक कोशिश है, जिनका व्यक्तित्व कभी महाराष्ट्र की राजनीति पर छाया हुआ था।

इस बात की कल्पना कुछ ही ने की थी कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना (यूबीटी) ने बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) चुनावों के लिए एमवीए से अलग होकर मनसे के साथ गठबंधन करेगी। यह कदम महाराष्ट्र की राजनीति में दूरगामी असर डाल सकता है।

यह गठबंधन सधे हुए चुनावी गणित पर आधारित है। दोनों ठाकरे मिलकर ''मराठी मानूस'' को साधने की कोशिश कर रहे हैं, जो मुंबई की आबादी का लगभग 40 प्रतिशत है, वहीं उनकी नज़र मुस्लिम समुदाय पर भी है, जो करीब 20 प्रतिशत है, के समर्थन पर भी उनकी नज़र है।

इस रणनीति के पीछे सीधा सा तर्क है: एकजुट ठाकरे खेमे का मानना है कि वे कांग्रेस की तुलना में भारतीय जनता पार्टी को हराने की बेहतर स्थिति में हैं, जिससे मुस्लिम समुदाय के पास उन्हें समर्थन देने के अलावा कोई और विकल्प नहीं बचेगा।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

ओडिशा में चार्टर्ड प्लेन की क्रैश लैंडिंग, 6 घायल

राउरकेला, 10 जनवरी। ओडिशा में शनिवार की दोपहर भुवनेश्वर से राउरकेला जा रहा इंडिया वन एयर का 9 सीटर प्लेन अचानक लैंडिंग के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस हादसे में 6 लोगों के घायल होने की खबर है। प्लेन

- **चार यात्री व दो पायलट वाले प्लेन में 4-5 किलोमीटर बाद ही खराबी आ गयी थी।**

राउरकेला के रघुनाथपल्ली इलाके में जल्दा ए ब्लॉक के पास क्रैश हुआ।

शुरुआती रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस हादसे में छह लोग घायल हुए हैं। राहत की बात है कि बड़ा हादसा होने से टल गया। प्लेन में सवार सभी लोगों को सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया है।

जानकारी के मुताबिक, इंडिया वन एयरलाइंस के विमान ने दोपहर करीब 1.30 बजे काटीबंधा कंसारा के पास एक खेत में इमरजेंसी लैंडिंग की। बताया

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

प्र.मंत्री ने राज्यों के मुख्य सचिवों की बैठक में उद्घोष किया, भारत अब ''रिफॉर्म एक्सप्रेस'' पर सवार हो गया है

इस उद्घोष से एक बात तो स्पष्ट हो गई कि वर्षों की सैद्धांतिक बहस अब समाप्त हो गई और भारत ने बिना हिचक के ''रिफॉर्म्स'' के रास्ते पर चलने को स्वीकार कर लिया है और अब इस बारे में कोई अनिश्चिता नहीं है

-सुकुमार साह-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 10 जनवरी। मुख्य सचिवों के सम्मेलन में प्रधानमंत्री का यह कहना कि भारत ''रिफॉर्म एक्सप्रेस में सवार हो चुका है'', केवल भाषण में दिखाया गया आत्मविश्वास नहीं है। यह इस सोच को दिखाता है कि लंबें समय से चल रहा यह विवाद, कि भारत को सुधारों की ज़रुरत है या नहीं, अब खत्म हो चुका है और अब काम है तेज़ी से अमल करने का। दशकों तक चली नीतिगत ढिलाई, छोटे-छोटे सुधार और राजनीतिक हिचकिचाहट के बाद यह जल्दबाजी की भावना समझ में आती है, और कई मायनों में यह बहुत पहले हो जानी चाहिए थी, लेकिन, फिर भी तेजी की इस बात को गंभीरता से जांचने की ज़रुरत है। सुधारों की रफ्तार अर्थव्यवस्था को ऊर्जा दे सकती है, लेकिन संतुलन के बिना तेज़ी से सीक्वैंसिंग, संस्थागत क्षमता और सामाजिक स्वीकार्यता जैसे कठित मुद्दे पैदा करती है।

परिभाषा के अनुसार, सुधार स्थापित व्यवस्थाओं को हिला देते हैं। जब इन्हें बहुत तेज़ी से आगे बढ़ाया जाता है, तो फायदे के साथ-साथ दबाव भी बढ़ जाते हैं। भारत का अपना अनुभव एक चेतावनी देने वाला सबक देता है। 1991 के ऐतिहासिक सुधार साहसिक थे, लेकिन वे व्यापक आर्थिक स्थिरता, राजनीतिक सहमति और प्रशासनिक बदलाव के ढांचे में लागू किए गए थे। उदारीकरण केवल घोषित नहीं हुआ, उसे धीरे-धीरे अपनाया गया। आज के सुधार कहीं ज़्यादा जटिल माहौल में हो रहे हैं, जहां वैश्विक अर्थव्यवस्था बंटी

- **अब रिफॉर्म के बारे में कोई शंका या शुबहा नहीं है। पर, रिफॉर्म्स (उदारीकरण) को कामयाब बनाने के लिए ''रेग्युलेटरी सिस्टम'' की जयादा जरुरत है।**
- **बार-बार कायदे कानून बदलना, कायदे कानून के बारे में बहस अभी अनिर्णित है तथा उदारीकरण की नीति को लागू करने के बारे में राज्यों की नीतियों में निर्विवाद प्रक्रिया रही है, अतः क्रियान्वयन समतल नहीं है।**
- **उदाहरण के लिए न्यूक्लियर एनर्जी में प्राइवेट पार्टियों को भूमिका देना, स्वागत योग्य निर्णय है, पर, प्राइवेट सैक्टर इस क्षेत्र में अपनी पूँजी लगाने के पहले ''पारदर्शिता'', विवाद या मतभेद निपटाने की साफ सुथरी व्यवस्था आदि पर कोई दुविधा नहीं चाहेगा।**
- **अतः किसी ने बड़े सटीक तरीके से इस बारे में कहा है कि ''प्र.मंत्री की ''रिफॉर्म एक्सप्रेस'' को मजबूत पटरियों की ज्यादा जरुरत है बनिस्पत जोर से बजने वाली सीटी की।''**

हुई है, बाहरी मांग धीमी है, सप्लाई चेन बदली जा रही है और देश के भीतर लगातार घरेलू असमानता बनी हुई है। इसलिए अमल केवल तकनीकी नहीं, बल्कि राजनीतिक और संस्थागत चुनौती भी है।

सरकार का भरोसे पर आधारित शासन और नियमों में ढील पर ज़ोर देना सही दिशा में है। भारत की जांच-प्रधान और अनुपालन-भारी (इंस्पैक्टर ड्रिवन) व्यवस्था लंबे समय से उद्यिमता (अपना कारोबार शुरु करने की प्रक्रिया) पर भारी बोझ डालती रही है, खासकर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों पर। टैक्स कानूनों को सरल बनाना, पुराने नियम हटाना और श्रम कानूनों को तर्कसंगत करना बहुत समय से ज़रूरी था। लेकिन ज़मीनी स्तर पर अमल अभी भी असमान है। कई कारोबारों के लिए समस्या इरादे की नहीं, बल्कि नियमों की अनिश्चितता की है, बार-बार बदलाव, अस्पष्ट व्याख्या और राज्यों में अलग-अलग ढंग से लागू होना। केवल सुधारों की घोषणा नहीं, बल्कि नियमों की स्थिरता ही जोखिम कम करती है और निवेश को बढ़ावा देती है।

कर सुधार इस तनाव को साफ तौर पर दिखाता है। सरल जी.एस.टी. ढांचा और आधुनिक आयकर व्यवस्था को सभी लोग जरुरी मानते हैं। लेकिन,

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

प्रधानमंत्री सोमनाथ पहुंचे

वेरावल, 10 जनवरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को अपने तीन दिवसीय गुजरात दौरे के तहत सोमनाथ पहुंचे, जहां वे सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में शामिल हुए। पीएम मोदी ओंकार जप में शामिल हुए और ड्रोन शो भी देखा। पीएम ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा,

- **वे रविवार को सुबह शौर्य यात्रा में भाग लेंगे।**

''सोमनाथ में आकर धन्य महसूस कर रहा हूं, जो हमारी सभ्यतागत साहस का एक गौरवशाली प्रतीक है। गर्मजोशी से स्वागत के लिए लोगों का आभारी हूं।

पीएम मोदी रविवार सुबह 9:45 बजे शौर्य यात्रा में हिस्सा लेंगे। यह एक औपचारिक जुलूस है जो सोमनाथ मंदिर की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति देने वालों को सम्मानित करने के लिए आयोजित किया गया है। यात्रा में 108 घोड़ों का एक प्रतीकात्मक जुलूस होगा, जो वीरता और बलिदान को दर्शाता है। इसके बाद, मोदी सुबह

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)